- =====
1. मोसमात चंदेश्वरी देवी, स्वर्गीय श्याम लाल गोप की पत्नी
 2. सबिता देवी, पति राम नरेश सिंह, पिता स्वर्गीय श्याम लाल गोप
दोनों निवासी, मखदुमपुर, थाना - खोड़ागंज, जिला-नालंदा

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. संयुक्त निदेशक, चकबन्दी-सह-अनुसंधान अधिकारी, चकबन्दी, पटना, बिहार
3. उप निदेशक, चकबन्दी, नालंदा
4. चकबन्दी अधिकारी, नालंदा
5. सुरेश गोप उर्फ सुरेन गोप पुत्र स्वर्गीय बासुदेव गोप, बैरा गाँव के निवासी-डाकघर कोचारा,
थाना-खोड़ागंज, जिला-नालंदा

..... उत्तरदातागण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री गौरी शंकर ठाकुर,

राज्य के अधिवक्ता: श्री मो. खुर्शीद आलम ए.ए.ज-12

प्रतिवादी संख्या 5 के लिए: मेसर्स मल्लिका मजूमदार और

प्रेम कुमार, अधिवक्ता-01

=====

बिहार जोत समेकन और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956 - धारा 3 - धारा 3 के तहत बिहार राज्य द्वारा लाई गई अधिसूचना - संबंधित क्षेत्र में जोत के समेकन के लिए एक योजना बनाने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए, नीचे की अदालत ने एक आदेश पारित किया कि अधिनियम की धारा 4 (सी) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर विभाजन का मुकदमा समाप्त हो जाएगा, यह भी उल्लेख किया गया था कि पार्टियां अपने विभाजन के लिए चकबंदी अधिकारियों से संपर्क कर सकती हैं। धारा 8 ए के तहत हिस्सेदारी - चकबंदी अधिकारी ने धारा 9(2) के तहत तैयार भूमि के रजिस्टर का मसौदा प्रकाशन और धारा 9 ए के तहत तैयार सिद्धांतों का विवरण प्रकाशित किया - किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई - योजना की पुष्टि की गई और धारा 13 के तहत निदेशक, चकबंदी को प्रस्तुत की गई अधिनियम - समेकन संचालन को बंद करने की घोषणा करने वाली अधिनियम की धारा 26 ए के तहत अधिसूचना अभी भी प्रतीक्षित थी - दो तरीके थे जिनके द्वारा समेकन संचालन को समाप्त या बंद किया जा सकता है - पहला प्रकाशन द्वारा अधिनियम की धारा 4 ए के तहत एक अधिसूचना जिसके द्वारा राज्य सरकार किसी भी समय अधिनियम की धारा 3 के तहत निर्दिष्ट पूरे क्षेत्र या उसके हिस्से के संबंध में की गई अधिसूचना को रद्द कर सकती है - दूसरा, धारा 26 ए के तहत एक अधिसूचना प्रकाशित करके योजना के तहत चकबंदी अभिलेख तैयार होने और रैयतों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, राज्य सरकार को आधिकारिक गजट में अधिसूचना प्रकाशित करनी होती है, जिसमें कहा गया है कि इकाई में चकबंदी कार्य बंद कर दिया गया है

कालिका कुआर उर्फ कालिका सिंह में दिया गया निर्णय को अलग कर दिया गया था और मामले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वापस भेज दिया गया था - अधिनियम की धारा 10-ए के तहत बनाई गई वैधानिक रोक, चकबंदी अधिकारियों को धारा 10-बी के तहत शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया था या नहीं - यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है चकबंदी अधिकारियों के पास अधिनियम की धारा 10-बी के तहत मौजा की पुष्टि के बाद भी होल्डिंग को विभाजित करने की ऐसी शक्ति नहीं होगी, अधिनियम की धारा 10-ए के तहत बनाई गई रोक के मद्देनजर-बार द्वारा बनाई गई धारा 10-ए निदेशक, चकबंदी द्वारा प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षण शक्तियों पर लागू नहीं होगी; और चूंकि मामला पार्टियों के अधिकार, स्वामित्व और हित और होल्डिंग के विभाजन

से संबंधित है जिसके लिए मुकदमा दायर किया गया था लेकिन पहले ही समाप्त हो चुका है -
मामला निदेशक, चकबंदी को भेज दिया गया है - अपील की अनुमति दी गई है।

1994 का सीडब्ल्यूजेसी नंबर 2589—संशोधित।

1979 बीबीजेसी 259[एफबी]—बरकरार/पुष्टि की गई 1989 पीएलजेआर 1203 [एफबी]—(2003)5
एससीसी 448 1984 बीबीजेसी 140 से प्रिथक रखा गया;

1985 पीएलजेआर 986; एआईआर 1985 पैट. 275; 1989 पीएलजेआर 170—संदर्भित।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

गणपूर्ति: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन)

तारीख: 29-08-2018

पक्षों को सुना।

यह अपील 1994 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2589 में इस न्यायालय के एक विद्वान
एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 24.07.2015 के निर्णय के खिलाफ निर्देशित है। उक्त
निर्णय द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने संयुक्त निदेशक-सह-अनुसंधान अधिकारी, चकबंदी,
बिहार, पटना द्वारा पारित दिनांक 06.02.1994 के आदेश को रद्द करने के बाद रिट याचिका को
मंजूरी दे दी है, जिसके द्वारा उन्होंने 1990 के अपील वाद संख्या 17 में उप निदेशक, चकबंदी,
नालंदा द्वारा पारित दिनांक 11.05.1992 के आदेश को रद्द कर दिया और 1989 के चकबंदी वाद
संख्या 53 में पारित दिनांक 15.12.1989 के चकबंदी अधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया।

अभिलेखों से निकले लघु तथ्यों की गणना इस प्रकार की गई है:-

ये अपीलार्थी, अर्थात् रिट याचिका के प्रत्यर्थी सं. 5 और 6 ने 1979 का विभाजन वाद सं. 140 में अवर न्यायाधीश, बिहारशरीफ की अदालत में संयुक्त परिवार की संपत्ति में एक तिहाई हिस्से को काटकर विभाजन के लिए दायर किया। बिहार राज्य द्वारा बिहार होल्डिंग्स के चकबंदी और विखंडन रोकथाम अधिनियम, 1956 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत लाई गई अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, संबंधित क्षेत्र में होल्डिंग्स के चकबंदी के लिए एक योजना बनाने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए, नीचे की अदालत ने एक आदेश पारित किया जिसमें घोषणा की गई कि अधिनियम की धारा 4 (सी) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विभाजन का मुकदमा समाप्त हो जाएगा। यह भी उल्लेख किया गया कि अधिनियम की धारा 8ए के तहत अपने हिस्से के विभाजन के लिए खुद चकबंदी प्राधिकरणों से संपर्क कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप, उपरोक्त प्रावधान के तहत 04.09.1980 को मुकदमा समाप्त हो गया। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चकबंदी अधिकारी ने अधिनियम की धारा 10 में निहित प्रावधानों के अनुसार धारा 9 (2) के तहत तैयार भूमि का रजिस्टर का मसौदा प्रकाशित किया और धारा 9ए के तहत तैयार किए गए सिद्धांतों का विवरण का मसौदा प्रकाशित किया और धारा 10 (2) के तहत आपत्ति आमंत्रित की गई थी। चूंकि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, इसलिए मसौदा योजना अधिनियम की धारा 11 के तहत तैयार की गई थी, जिसे अंततः अधिनियम की धारा 12 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया गया था और चूंकि किसी ने भी अधिनियम की धारा 12ए के तहत कोई आवेदन दायर करके इस पर आपत्ति नहीं जताई थी, इसलिए योजना की पुष्टि की गई और अधिनियम की धारा 13 के तहत निदेशक, चकबंदी को प्रस्तुत की गई। इसके बाद, रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रमाण पत्र आदि भी वितरित किए गए, हालांकि, अधिनियम की धारा 26ए के तहत चकबंदी संचालन को बंद करने की घोषणा करने वाली अधिसूचना का अभी भी इंतजार था। इसके बाद, वर्ष 1999 में, अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 10-बी के तहत चकबंदी अधिकारी के समक्ष विभाजन का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया और यह भी दावा किया कि संपत्ति में स्वर्गीय हेमराज गोप की कोई स्व-अर्जित संपत्ति शामिल नहीं है, क्योंकि उनके पास इस तरह की संपत्ति नहीं थी। यह दावा किया गया था कि हेमराज गोप अपने पोते के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख के आधार पर संयुक्त परिवार की संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर

रहे थे। चूंकि उस समय वह नाबालिग था, इसलिए बिक्री विलेख अमान्य और धोखाधड़ी वाला होगा क्योंकि कोई भी नाबालिग संपत्तियों को हस्तांतरित या प्राप्त नहीं कर सकता और वास्तव में, स्वर्गीय हेमराज गोप, जो विक्रेता थे, अपने नाबालिग पोते, यानी विक्रेता के संरक्षक थे, और इस तरह, धोखाधड़ी की गई थी और इस तरह के अमान्य/शून्य लेनदेन के आधार पर, यह नहीं माना जा सकता है कि यह उनके पोते की स्व-अर्जित संपत्ति थी। कई अन्य बिंदु भी शामिल थे, उदाहरण के लिए, कि अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि वे सह-मालिक हैं और संयुक्त रूप से और सामूहिक रूप से संयुक्त परिवार की संपत्ति के मालिक हैं।

अधिनियम की धारा 10-बी के तहत दायर की गई ऐसी याचिका पर, 1989 का चकबंदी मामला संख्या 53 दर्ज किया गया था। चकबंदी अधिकारी ने कुछ चाकों के संबंध में अपीलकर्ताओं-प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के दावे को खारिज कर दिया, हालांकि, अन्य के संबंध में, उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम बासुदेव गोप के साथ आधे सह-भागीदारों के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। अपीलार्थी-प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 द्वारा 1990 की चकबंदी अपील संख्या 17 वाली अपील दायर की गई थी। रिट याचिकाकर्ता (इसमें प्रतिवादी) ने उप निदेशक, समेकन के समक्ष भी अपील दायर की, जिसे 04/1990 के रूप में क्रमांकित किया गया था। उप निदेशक, चकबंदी ने चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि अधिनियम की धारा 10-ए के तहत किसी भी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए बनाए गए प्रतिबंध के बावजूद इसे पारित किया गया था। इसके बाद, 1992 का संशोधन सं. 273 निदेशक, चकबंदी के समक्ष दायर किया गया था, जिसे अंततः अनुसंधान अधिकारी, चकबंदी निदेशालय द्वारा यह मानते हुए तय किया गया था कि अपीलीय प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 10-ए के तहत बनाए गए अवरोध के संदर्भ में दावे को खारिज नहीं करना चाहिए था क्योंकि उक्त प्रतिबंध के संचालन से रैयत का अधिकार और स्वामित्व प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो सकता है।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई इस दलील को स्वीकार कर लिया है कि एक बार अधिनियम की धारा 9 के तहत तैयार किए गए मानचित्र या रजिस्टर में की गई किसी भी प्रविष्टि या संबंधित क्षेत्र से संबंधित धारा 9-ए के तहत तैयार किए

गए सदस्यों के बयान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई थी, जिसे अधिनियम की धारा 10 के तहत उठाया जाना चाहिए था, किसी को भी उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी यदि चकबंदी अधिकारी को मामले की सुनवाई करने की अनुमति नहीं दी गई थी और समेकन कार्यवाही के किसी भी बाद के चरण में। इस न्यायालय की एक खंड पीठ के निर्णय का संदर्भ देने के बाद जगन्नाथ ठाकुर और एक अन्य बनाम में प्रस्तुत किया गया। बिहार राज्य और अन्य [1984 बी. बी. सी. जे. 140], एकल न्यायाधीश ने सीखा है इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अपनी इस दलील में सही था कि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने धारा 10-ए के तहत बनाए गए वैधानिक प्रतिबंध के सवाल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है और इसे दरकिनार करते हुए, उसने समेकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया। हालाँकि, निर्णय में आगे यह अभिलिखित किया गया है कि रिट याचिकाकर्ताओं के वकील भी यह सूचित करने की स्थिति में नहीं थे कि क्या अधिनियम की धारा 26 ए के तहत कोई अधिसूचना जारी की गई है या संबंधित क्षेत्र के संबंध में नहीं। मामले की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, उन्होंने पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अधिनियम की धारा 26 ए के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, तो प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा प्रस्तुत मुकदमा स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाएगा और पक्षकारों के बीच अंतर-विवाद, स्वामित्व के संबंध में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सक्षम अधिकार क्षेत्र के दीवानी न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

जहाँ तक अधिनियम की धारा 10-ए के तहत बनाए गए वैधानिक प्रतिबंध के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण का संबंध है, वही सही प्रतीत होता है। इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 10-ए के तहत प्रतिबंध लागू था और अधिनियम की धारा 10-बी के तहत एक याचिका, ऐसे मामले में, बनाए रखने योग्य थी या नहीं, जिसे पुनरीक्षण अदालत द्वारा तय किया जाना आवश्यक था। हालाँकि, असली सवाल यह है कि क्या मामला अधिनियम की धारा 35 के तहत पुनरीक्षण अदालत तक गया है, इस तथ्य के साथ कि अधीनस्थ न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया था कि विभाजन वाद अधिनियम की धारा 4 (सी) के तहत समाप्त हो जाएगा और पक्षकार स्वयं समेकन प्राधिकरणों द्वारा अपना

विभाजन करवा सकते हैं, क्या निदेशक, समेकन स्वयं अधिनियम की धारा 35 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे या नहीं? क्या अधिनियम की धारा 10-ए निदेशक, समेकन की शक्तियों के लिए भी बाधा के रूप में खड़ी होगी?

अब यह सर्वविदित है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के तहत इस उद्देश्य के लिए अपने इरादे की घोषणा करने के बाद समेकन अभियान शुरू किया गया है। दो तरीके हैं जिनके द्वारा समेकन संचालन को समाप्त या बंद किया जा सकता है। पहला अधिनियम की धारा 4 ए के तहत एक अधिसूचना प्रकाशित करना है क्योंकि इस तरह के प्रावधान के तहत राज्य सरकार को किसी भी समय अधिनियम की धारा 3 के तहत की गई अधिसूचना को उसमें निर्दिष्ट पूरे या क्षेत्र के हिस्से के संबंध में रद्द करने की शक्ति मिली है। दूसरा तरीका यह है कि समेकन रिकॉर्ड तैयार होने और योजना के तहत रैयत को हस्तांतरण के प्रमाण पत्र जारी होने के बाद अधिनियम की धारा 26 ए के तहत एक अधिसूचना प्रकाशित की जाए। राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करनी होगी जिसमें कहा गया है कि इकाई में समेकन कार्य बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद क्या होगा, इस पर इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ द्वारा विचार किया गया, जिसे **रामकृत सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य**। [1979 बीबीसीजे 259] में प्रस्तुत किया गया था। पूर्ण पीठ ने कहा है कि अधिनियम की धारा 26 ए के तहत अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा गांव या क्षेत्र में समेकन के करीब आने के बाद, समाप्त किया गया मुकदमा पुनर्जीवित होगा, लेकिन उन मुकदमों के पुनरुद्धार से कोई समस्या पैदा नहीं होगी क्योंकि जहां तक समेकन कार्यवाही के तहत आने वाली किसी भी भूमि में अधिकारों या हितों का संबंध है, समेकन कार्यवाही में लिए गए निर्णयों के अनुरूप मुकदमा तय करना होगा। हालांकि, बाद में पूरा बेंच **कालिका कुर उर्फ कालिका सिंह बनाम में प्रस्तुत किया गया। बिहार और अन्य राज्य** [1989 पी. एल. जे. आर. 1203] ने माना है कि चकबंदी प्राधिकरण सीमित अधिकारिता का न्यायालय होने के कारण, अधिनियम की धारा 26 ए के तहत अधिसूचना के बाद, समाप्त किया गया मुकदमा फिर से शुरू हो जाएगा और संबंधित पक्ष समेकन प्राधिकरण द्वारा निर्णय के बाद भी सक्षम अधिकारिता के दीवानी न्यायालय द्वारा अपना निर्णय ले सकते हैं। पूर्ण पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि पूर्ववर्ती पूर्ण पीठ, अर्थात्, में दिया गया निर्णय **रामकृत सिंह (ऊपर)**

इनक्यूरियम के अनुसार होना चाहिए क्योंकि यह नहीं था इस मुद्दे पर विचार करें कि समेकन प्राधिकरण सीमित अधिकार क्षेत्र के न्यायालय हैं, इसलिए, उनके निर्णय दीवानी न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं बनाए जा सकते हैं।

हालाँकि, इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बिहार राज्य और अन्य बनाम प्रस्तुत मामले में चुनौती दी गई थी। कालिका कुमार उर्फ कालिका सिंह [(2003) 5 एस. सी. सी. 448] द.। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और इससे जुड़े मुद्दे में यह अभिनिर्धारित किया कि पूर्ण पीठ पूर्ण पीठ के पहले के निर्णय को खारिज नहीं कर सकती थी और यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि पूर्व पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में बाद की पूर्ण पीठ द्वारा कोई विचार नहीं किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि निर्णय को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार, कालिका कुर @कालिका सिंह (ऊपर) में दिए गए निर्णय को दरकिनार कर दिया गया और मामले को रिमांड पर ले लिया गया और इस मुद्दे पर एक उपयुक्त पीठ द्वारा विचार किया जाना है।

हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश को केवल पुनरीक्षण आदेश को दरकिनार करने के बाद मामले को समाप्त नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसे इस मुद्दे के उत्तर के रूप में प्रत्येक पहलू पर विचार करने के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकरण को भेज दिया जाना चाहिए था कि मुकदमे के पुनरुत्थान पर धारा 26ए के तहत अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद क्या होगा, यह कल के गर्भ में है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिमांड के बाद उपयुक्त पीठ द्वारा अभी तक इसका निर्णय नहीं लिया गया है।

यहाँ एक सवाल उठेगा कि क्या निदेशक, समेकन को अधिनियम की धारा 35 के तहत इस मुद्दे को लेने का अधिकार और अधिनियम की धारा 10-ए के तहत एक वैधानिक प्रतिबंध होने के बावजूद मामले को उठाएं और इस पर निर्णय लें? इस मुद्दे को खुला रखा गया था जे. अगरनाथ ठाकुर (ऊपर) में डिवीजन बेंच जिस पर रिट याचिकाकर्ताओं-प्रत्यर्थियों द्वारा भरोसा किया गया है और जो विवादित निर्णय पारित करने का आधार बनता है। जे. अगरनाथ ठाकुर (ऊपर) मामले में डिवीजन बेंच के फैसले के प्रासंगिक अंशों को बेहतर सराहना के लिए नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

“11. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 35 को देखते हुए समेकन निदेशक उप निदेशक द्वारा पारित आदेश पारित कर सकता था। अधिनियम की धारा 35 इस प्रकार है:--

समेकन निदेशक अपने स्वयं के प्रस्ताव से या किसी पक्ष के आवेदन पर या किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किए जा रहे संदर्भ पर, कार्यवाही की नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से ऐसे प्राधिकारी द्वारा तय किए गए किसी मामले या की गई कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकता है; या, मामले या कार्यवाही में ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में, और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, मामले या कार्यवाही में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

धारा 35 समेकन निदेशक को पर्यवेक्षी शक्ति प्रदान करती है, जो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी भी पक्ष के आवेदन पर लिए किसी भी मामले के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकता है। किसी भी आदेश की नियमितता, शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से और जैसा वह उचित समझता है वैसा आदेश पारित कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 35 के तहत शक्ति बहुत व्यापक है जिसका उपयोग समेकन निदेशक द्वारा उसमें उल्लिखित शर्तों के तहत किया जाना है, लेकिन तत्काल मामले में, शक्ति का प्रयोग उप निदेशक द्वारा किया गया है न कि अधिनियम की धारा 35 के तहत निदेशक द्वारा।

11. इसके अलावा, धारा 35 में कोई गैर-जिद्दी खंड नहीं है। इस प्रकार, इसका उत्तर देना आसान नहीं है कि क्या धारा 35 का प्रावधान अधिनियम की धारा 10-ए को ओवरराइड करेगा। मामला अलग होता अगर धारा 35 में एक खंड होता जिसमें कहा गया होता कि "अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद"। मैं बता सकता हूँ कि धारा 10-डी के तहत, जो वर्ष 1982 में पेश की गई है, "धारा 10-ए के प्रावधानों के बावजूद" शब्द हैं।

12. हालाँकि, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आग्रह किया कि इस मामले में यह निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या धारा 10-ए के तहत प्रतिबंध धारा 35 के तहत समेकन निदेशक की शक्ति पर भी काम करता है, जिस पर किसी अन्य उपयुक्त मामले में विचार किया जा सकता है। यह रवैया विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा इसलिए अपनाया गया था क्योंकि अधिनियम की धारा 35 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए समेकन निदेशक द्वारा विवादित आदेश पारित नहीं किया गया है। उन्होंने केवल उप निदेशक के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

”हालाँकि, बाद में, इस न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने **शिव कुमार ठाकुर बनाम** में दिया गया निर्णय। **बिहार और अन्न राज्य। [1985 पी. एल. जे. आर. 986]** ने स्पष्ट रूप से कहा था कि धारा 35 अधिनियम की धारा 10-ए के तहत सृजित शक्ति पर हावी होगी और निदेशक, अपनी पुनरीक्षण शक्ति में समेकन कार्यवाही की नियमितता और इसकी शुद्धता और इसकी वैधता के अलावा किसी भी आदेश की औचित्य की जांच कर सकता है। **श्याम बिहार** के एक अन्य एकल न्यायाधीश ने भी यही विचार रखा था। **उपाध्याय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य। [एयर] 1985 पैट 275]**। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्वान एकल न्यायाधीश, जो डिवीजन के फैसले के लेखक थे **जगन्नाथ ठाकुर (ऊपर)** की पीठ ने बनाए गए प्रतिबंध की पुष्टि की समेकन कार्यवाही में धारा 10-ए द्वारा लेकिन निदेशक की पुनरीक्षण शक्तियों पर इसके प्रभाव के मुद्दे को रखते हुए, अधिनियम की धारा 35 के तहत समेकन पूरी तरह से खुला था, उपरोक्त मामले में एकल न्यायाधीश के रूप में निर्णय लिया था कि धारा 10-ए निदेशक, समेकन की शक्तियों पर बाधा के रूप में काम नहीं करेगी, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए आदेश या कार्यवाही में किसी भी गलती को सुधारने के लिए अधिनियम की धारा 35 के तहत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती **श्रीमती लीला देवी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य** मामले में एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा समान दृष्टिकोण लिया गया था। **[1989 पीएलजेआर 170]**। मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक कदम आगे बढ़कर यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि पुनरीक्षण प्राधिकरण, अर्थात् निदेशक, समेकन के समक्ष कोई

कार्यवाही लंबित थी, उस समय जब समेकन कार्यों को बंद करने की घोषणा करने वाली अधिनियम की धारा 26ए की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, तब भी अधिनियम की धारा 26ए की उप-धारा (2) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, निदेशक को अंतिम आदेश घोषित करके पुनरीक्षण कार्यवाही को पूरा करने का अधिकार होगा।

ऐसी स्थिति में, जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के उस पहलू के बारे में कहा है कि क्या अधिनियम की धारा 10-ए के तहत बनाए गए वैधानिक प्रतिबंध को देखते हुए, समेकन अधिकारियों को धारा 10-बी के तहत शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया था या नहीं, तो मामले को अनिवार्य रूप से उस हिसाब से भी रिमांड पर लेने की आवश्यकता थी क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंततः मुद्दे का जवाब नहीं दिया है।

हमारे विचार में, वह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है क्योंकि समेकन प्राधिकरणों के पास अधिनियम की धारा 10-ए के तहत बनाए गए प्रतिबंध को देखते हुए अधिनियम की धारा 10-बी के तहत मौज़ा की पुष्टि के बाद भी होल्डिंग को विभाजित करने की ऐसी शक्ति नहीं होगी। हालाँकि, चूंकि मामला निदेशक, समेकन तक गया है और यह 2016 के **शिव कुमार ठाकुर (ऊपर)** और **श्याम बिहार उपाध्याय (ऊपर)** मामले में यह कहा गया कि धारा 10-ए द्वारा सृजित बाँधायें निदेशक, समेकन द्वारा प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षण शक्तियों पर प्रभावी नहीं होगा, और चूंकि मामला पक्षों के अधिकार, स्वामित्व और हित और स्वामित्व के विभाजन से संबंधित है, जिसके लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन पहले ही समाप्त हो चुका है, हमारे विचार में, उपरोक्त विचारों के साथ पूरी तरह से सहमत होने के कारण, यह समेकन निदेशक को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मामले में एक नया निर्णय लेने के लिए रिमांड के लिए एक उपयुक्त मामला है, क्योंकि हमारा विचार है कि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने यांत्रिक तरीके से एक तर्कपूर्ण आदेश पारित नहीं किया है, इसलिए उसने केवल निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं - समेकन अधिकारी के विचारों की पुष्टि की। स्वामित्व और स्वामित्व के विभाजन के जटिल प्रश्न का निर्णय इस तरह के यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता है। श्रीमती **लीला देवी (ऊपर)**, में दिए गए निर्णय को देखते हुए, हालांकि दोनों पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि धारा 26ए के तहत अधिसूचना अभी भी प्रतीक्षित है, हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उसमें दिए गए निर्णय को देखते

हुए, धारा 26 ए(1) के तहत अधिसूचना के बाद भी, उपरोक्त प्रावधान की उप-धारा (2) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, वर्तमान मामले में समेकन निदेशक, द्वारा पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि यह भारत संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर एक रिट याचिका में इस न्यायालय के समक्ष के लम्बित रही है, नतीजतन, इस अपील को ऊपर बताए गए हद तक अनुमति दी जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को इस हद तक संशोधित किया जाता है और मामला निदेशक, समेकन को भेज दिया जाता है ताकि संबंधित पक्षों को अपनी योग्यता और कानून के अनुसार उचित अवसर देने के बाद एक नया आदेश पारित किया जा सके। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(मुकेश आर. शाह, मुख्य न्यायाधीश)

(डॉ. रवि रंजन, न्यायाधीश)

एसपीडी/- संजय

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।